



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 22-2017] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 30, 2017 (JYAISTHA 8, 1939 SAKA)

PART III

Notifications by High Court, Advertisement, Notices and Change of Name etc.

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

दिनांक 20 मई, 2017

संख्या प्रा० 83286.— हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम 13) की धारा 54 के (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा यादी क्रमांक 07/02/2017-2TCP दिनांक 11/04/2017 द्वारा सूचित राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसके द्वारा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (भूमि तथा भवन निपटान) विनियम, 1978 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये विनियम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (भूमि तथा भवन निपटान) संशोधन विनियम 2017 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (भूमि तथा भवन निपटान) विनियम, 1978 में, विनियम 6 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“उच्चतम बोलीदाता द्वारा भुगतान, ई-नीलामी के लिए अधिसूचित निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार किया जाएगा। जिसमें असफल होने पर पहले जमा की गई राशि प्राधिकरण द्वारा जब्त की जाएगी तथा सफल बोलीदाता का नीलाम की गई भूमि या भवन पर कोई दावा नहीं होगा। सफल बोली दाता को सीसी-आर, सीसी-बी तथा सीसी-जी के प्रारूप में आबंटन पत्र जारी किया जाएगा।”
3. प्रारूप ‘सी सी-आर, ‘सी सी-बी’ और सी सी-जी’ का प्रारूप संलग्न है।

विकास गुप्ता,
मुख्य प्रशासक,
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण।

पंजीकृत

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

सम्पदा कार्यालय

प्रारूप "सी.सी.आर."

(देखिये विनियम 6 (2))

(छोड़े गए रिहायशी प्लॉटों के लिए ई-नीलामी के माध्यम से पूर्ण स्वामित्व आधार पर किए गए आबंटन के लिए आबंटन पत्र का प्रारूप)

सेवा में

आबंटियों की
तस्वीर

यादि क्रमांक : ई.ओ. () /

दिनांक

विषय :- पूर्ण स्वामित्व आधार पर शहरी सम्पदा के सैक्टर में स्थल/भवन संख्या पिछले शेष बचे रिहायशी प्लॉटों की बिक्री द्वारा आबंटन।

यह जैसा है जहां के आधार पर स्वीकृत के सैक्टर में स्थल/भवन नम्बर के लिए आपकी बोली के संदर्भ में है।

2. शहरी सम्पदा के सैक्टर में प्लॉट/भवन नम्बर के लिए आप की बोली स्वीकृत कर ली गई है तथा प्लॉट/भवन जिसके ब्योरे नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार तथा हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (जिसे, इसमें, इसके बाद अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) तथा उसके अधीन लागू तथा समय समय पर यथा संशोधित नियमों/विनियमों/संहिता/हिदायतों/मार्गदर्शनों के उपबन्धों के अधीन जिसमें नीलामी के समय पर पहले ही घोषित निबन्धनों तथा शर्तें शामिल हैं तथा आप द्वारा स्वीकृत की गई है, के अनुसार पूर्ण स्वामित्व आधार पर आप को आबंटित किया गया है :-

सैक्टर नम्बर	शहरी सम्पदा का नाम	प्लॉट/ भवन नम्बर	नीलामी के समय पर यथा अधिसूचित लगभग परिमाण या वर्णन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	कीमत (रुपए में)

3. बोली राशि के लिए आप द्वारा जमा रुपए की राशि प्लॉट/भवन की कीमत के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।
4. इसके अतिरिक्त, आप से नीलामी की तिथि से 45 दिन की अवधि के भीतर अर्थात् (.....तक)/- आप द्वारा पहले ही जमा राशि के साथ उक्त प्लॉट/भवन की कुल बोली कीमत का 25 % होगी, जमा कराने का अनुरोध किया जाता है। उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त राशि जमा कराने में असफल होने की दशा में, आबंटन रद्द हो जाएगा तथा बोली के समय पर जमा 10 % बोली राशि प्राधिकरण में जब्त हो जाएगी जिसके विरुद्ध आपका हानियों के लिए आपका कोई दावा नहीं होगा।
5. उसके पश्चात, उक्त प्लॉट/भवन की कुल बोली राशि की बाकी की 75 % राशि अर्थात्/- रुपए बिना ब्याज के नीलामी की तिथि से 120 दिन के भीतर एकमुश्त भुगतान की जाएगी, जिसमें असफल होने पर आबंटन बिना किसी नोटिस के रद्द हो जाएगा तथा आप द्वारा जमा 25 % बोली राशि जब्त हो जाएगी तथा आपका हानियों के लिए कोई भी दावा नहीं होगा।
6. पूर्वोक्त अदायगी के भुगतान के लिए अलग से कोई भी नोटिस नहीं भेजा जाएगा।
7. सभी भुगतान हुडा वैबसाईट पर आनलाईन पद्धति के द्वारा या हुडा वैबसाईट पर पीपीएम प्रणाली से चालान उत्पन्न करके प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से आफ लाईन पद्धति से किया जाएगा।

8. जब कभी यदि आप नीलामी की तिथि से 120 दिन की अवधि के भीतर किसी समय पर स्थल अर्पित करते हैं, तो सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी, हुडा ऐसे अर्पण के आवेदन की तिथि तक देय ब्याज तथा शास्ति, यदि कोई हो, सहित कुल प्रतिफल धन राशि का 10 % काटने के बाद राशि वापस करेगा। तथापि, कोई भी ब्याज वापस की जाने वाली ऐसी राशि पर भुगतानयोग्य नहीं होगा।
9. अर्पण के लिए निवेदन हुडा द्वारा आबंटित लागईन आई डी तथा पासवर्ड का प्रयोग करते हुए हुडा वैबसाइट पर पीपीएम प्रणाली पर आनलाईन प्रस्तुत किया जाना है। किसी अन्य रीति द्वारा अर्पण स्वीकार्य नहीं होगा।
10. स्थल/प्लॉट का कब्जा आप द्वारा हुडा में केवल सम्पूर्ण बोली राशि का भुगतान करने के बाद ही दिया जाएगा। यदि प्लॉट का कब्जा सम्पूर्ण बोली राशि के जमा करने के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर नहीं दिया गया है, तो हुडा कब्जा देने की तिथि तक आप द्वारा जमा राशि पर 5.5 % प्रतिवर्ष (या जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए) की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। तथापि, ऐसा ब्याज यथा पूर्वोक्त 30 दिन की समाप्ति के बाद तथा कब्जा देने की तिथि तक संगणित अवधि के लिए भुगतानयोग्य होगा।
11. तथापि, यदि न्यायालय द्वारा स्थगन या वाद या हुडा के नियन्त्रण से बाहर किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण, हुडा सम्पूर्ण (100 %) उच्चतम बोली राशि जमा करने के बाद तीन मास के भीतर प्लॉट/स्थल का कब्जा देने में योग्य नहीं है, तो आप द्वारा जमा सम्पूर्ण राशि वापस लौटाई जाएगी। आप का इस स्थल/स्थलों या किसी अन्य स्थल/स्थलों पर कोई दावा नहीं होगा।
12. किसी शर्त के उल्लंघन की घटना में, सम्पदा अधिकारी, हुडा अधिनियम की धारा 17 के उपबन्धों के अनुसार स्थल पुनः ग्रहण कर सकता है तथा जमा की गई राशि कुल प्रतिफल राशि का 10 %, पुनः ग्रहण की तिथि तक भुगतानयोग्य ब्याज तथा अन्य देयों को जब्त करने के बाद वापस लौटाई जाएगी। वापस की जाने वाली ऐसी राशि पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा।
13. पुनः ग्रहण के बाद, आप उसकी अपनी स्वयं की लागत पर पुनः ग्रहण आदेश की तीन मास की अवधि के भीतर संरचना/मलबा/फिक्सचर, यदि कोई हो, हटाने के लिए स्वतन्त्र होंगे, जिसमें असफल होने पर समय बोलीदाता की लागत पर हुडा द्वारा हटवाया जाएगा।
14. स्थल, स्थल की बिक्री के कारण हुडा को देय ब्याज तथा अन्य राशि सहित सम्पूर्ण बोली धन राशि का भुगतान करने तक तथा आप के पक्ष में हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करने तक नियंत्रण हुडा के पास रहेगा। आप को हस्तान्तरण विलेख के निष्पादन के बाद भी सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी, हुडा की पूर्व लिखित अनुमति के बिना स्थल का अन्तरण करने तथा उस पर कोई अधिकार/हक/हित सृजित करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तथापि, आप केवल प्लॉट के देयों इत्यादि सहित कीमत के भुगतान के लिए प्लॉट के विरुद्ध कर्ज राशि प्राप्त करने के लिए स्थल को गिरवी रख सकते हैं या उस पर कोई अधिकार/हित सृजित कर सकते हैं किन्तु सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी, हुडा की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी।
15. बोली राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, इत्यादि के शत प्रतिशत भुगतान पर, आप निर्धारित प्ररूप में तथा ऐसी रीति में, जैसा सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी, हुडा द्वारा निदेशित किया जाए, अपने पक्ष में हस्तान्तरण विलेख तैयार कराएंगे। हस्तान्तरण विलेख प्लॉट/भवन की सम्पूर्ण कीमत का भुगतान करने के एक वर्ष के भीतर निष्पादित किया जाएगा। तथापि, इसमें विनिर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि में हस्तान्तरण विलेख का इस प्रकार निष्पादन करने में असफल रहने के मामले में, हस्तान्तरण विलेख इसके निष्पादन के वर्ष में अभिभावी कलक्टर दरों पर या नीलामी कीमत, जो भी अधिक हो, संगणित स्थल के मूल्य पर स्टाम्प शुल्क पर निष्पादनयोग्य होगा। पंजीकरण तथा स्टाम्प शुल्क के प्रभार सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किए जाएंगे।
16. स्थल का प्रयोग उस प्रयोजन जिस के लिए यह आबंटित किया गया है, से अन्यथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। स्थल पर कोई भी आपत्तिजनक (हानिकर) कार्यकलाप नहीं किया जाएगा। तथापि, हुडा विनियम, 1978 तथा इसके अधीन जारी की गई तथा समय-समय पर संशोधित पालिसी के अनुसार, उपद्रव व्यावसायिक परामर्शी सेवाएं अनुमत हैं।
17. स्थल को किन्हीं भी परिस्थितियों में उप विभाजित या विखण्डित नहीं किया जाएगा। तथापि, स्वतन्त्र मंजिलों का पंजीकरण पालिसी के अनुसार अनुमत है।
18. आप को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कथित स्थल/भवन पर अधिरोपित या निर्धारित सभी साधारण तथा स्थानीय करों, दरों या उपकरों का भुगतान करना होगा।
19. आप को आबंटन के समय पर आप के प्लॉट में विद्यमान किसी निर्माण सामग्री, ईंट, संरचना तथा कम्पाउंड दीवार इत्यादि का अलग से भुगतान करना होगा जिस का मुआवजा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तथा भुगतान किया गया है, यदि आप उसका प्रयोग करना चाहते हैं।
20. प्राधिकरण असमतल स्थलों को समतल करने के लिए जिम्मेवार नहीं होगा तथा स्थल जैसा है जहां है आधार पर नीलाम किए गए हैं।

21. नीलाम स्थल पर भवन के निर्माण के लिए शर्तें स्थल की जोनिंग प्लान द्वारा तथा समय-समय पर बनाई गई तथा संशोधित हरियाणा भवन संहिता, 2016/2017 के अनुसार शासित होंगी। भवन सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी, हुडा से नक्शा स्वीकृत कराने के बाद ही निर्मित किया जाएगा। आप सम्पदा अधिकारी की पूर्व/सुस्पष्ट लिखित अनुमति के बिना स्थल पर निर्मित ढांचे में कोई परिवर्तन/परिवर्धन नहीं करेगा।
22. यह आबंटन हरियाणा भवन संहिता 2016 के लागू होने से पूर्व विद्यमान पुराने एफ.ए.आर. पर किया जाएगा तथा हरियाणा भवन संहिता, 2016 के अधीन अनुज्ञेय अतिरिक्त एफ ए आर समय-समय पर सरकार द्वारा यथा अनुमोदित प्रभारों के भुगतान पर आबंटिती द्वारा अलग रूप से खरीदा जाना होगा।

प्लॉट आकार	प्रत्येक मंजिल पर अधिकतम अनुज्ञेय क्षेत्र	एफएआर		
		अब आबंटित किया जा रहा है	अतिरिक्त खरीद योग्य	कुल
3 मरला तक	66	1.65	0.33	1.98
4 मरला	66	1.65	0.33	1.98
6 मरला	66	1.45	0.53	1.98
8 मरला	66	1.45	0.53	1.98
10 मरला	66	1.45	0.53	1.98
14 मरला	60	1.30	0.50	1.80
1 कनाल	60	1.20	0.60	1.80
2 कनाल	60	1.00	0.80	1.80

23. आप को भवन के निर्माण को शासित करने वाले विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्रस्तावित भवन का नक्शा स्वीकृत कराने के बाद कब्जे देने की तिथि के दो वर्ष के भीतर निर्माण पूरा करना होगा। समय सीमा समय-समय पर हुडा द्वारा यथा निर्धारित विस्तार फीस के भुगतान की शर्त के अधीन सम्पदा अधिकारी द्वारा विस्तारयोग्य है, अन्यथा यह प्लॉट पुनः ग्रहण किए जाने के लिए उत्तरदायी है तथा इसके सम्बन्ध में भुगतान की गई सम्पूर्ण धनराशि या उसका भाग, यदि कोई हो, हुडा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी है। आप सम्पदा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भवन का निर्माण या कोई परिवर्तन/परिवर्धन नहीं करेंगे।
24. प्राधिकरण ऐसे सभी अधिकारों तथा शक्तियों सहित कथित स्थल में या के नीचे सभी खान तथा खनिज जो भी हों, को लिए स्वयं आरक्षित रखता है जो कथित स्थल के सभी या किसी भाग की किसी सतह या कोई भूमिगत कार्य करने तथा सतह से निकालने तथा ऐसी सभी बातों को करने के प्रयोजन के लिए कथित स्थल पर गड़्ढे खोदने, भवन बनाने, लाईनों का निर्माण करने तथा सामान्यतः उचित तथा सही प्रयोग करने की शक्ति सहित ऐसी रीति में ऐसे सभी समयों पर उसकी छानबीन करने, कार्य करने, प्राप्त करने, हटाने तथा उपभोग करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा समीचीन हो जो उसमें दिए गए अपवादों तथा आरक्षणों के सम्पूर्ण उपयोग के लिए सुविधाजनक या आवश्यक हो :
- परन्तु आप सतह का प्राधिकरण द्वारा अधिभोग के लिए तथा आप तथा प्राधिकरण के बीच किए गए करार के अनुसार ऐसे कार्यों या कार्य करने या भाड़े पर देने से कथित भूमि की सतह या भवन को की गई हानि के लिए ऐसे भुगतान प्राधिकरण से प्राप्त करने को हकदार होंगे या ऐसे करार में असफल होने पर जैसा मध्यस्थता के निर्देश से पता लगाया जाएगा।
25. प्राधिकरण यह पता लगाने के प्रयोजन के लिए कि आबंटिती उक्त अधिनियम के अधीन लागू नियम/संहिता/विनियमों के अधीन पालन की जाने वाली शर्तों को विधिवत पूरा तथा पालन करता है, कथित भूमि/उस पर निर्मित भवन में या उसके किसी भाग पर लिखित में 24 घण्टे के बाद सभी युक्तियुक्त समयों पर तथा युक्तियुक्त रीति में अपने अधिकारियों तथा नौकरों द्वारा प्रवेश कर सकता है।

26. प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या नौकरों के माध्यम से सभी कार्य तथा बातें करने के लिए सभी समयों पर पूरे अधिकार शक्ति तथा प्राधिकार होगा जो अधिरोपित सभी या किन्हीं निबन्धनों, शर्तों तथा आरक्षणों को लागू करने, अनुपालन तथा कथित भूमि/भवन पर प्रथम प्रभार, ऐसे सभी या कोई कार्य तथा बातें करने की लागत तथा उसके सम्बन्ध में या उसमें या उससे सम्बन्धित किसी रूप में उपगत सभी लागतों के रूप में आप से वसूल करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो।
27. इस आबंटन के विषय में के सम्बन्ध में या किसी रूप में किसी भी प्रकार से उत्पन्न सभी विवाद तथा झगड़े मुख्य प्रशासक के एक मात्र मध्यस्थता या उस द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को निर्दिष्ट किए जाएंगे। ऐसी नियुक्ति के लिए कोई आक्षेप नहीं होगा कि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ सरकारी कर्मचारी है या प्राधिकरण को कोई अधिकारी है कि उसने मामले का निपटान किया था जिससे यह आबंटन ऐसे सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में उसकी ड्यूटी के सिलसिले में सम्बन्धित है, उसने विवाद या झगड़े में सभी या किन्हीं विषयों में अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा तथा सम्बन्धित पक्षकारों पर बाध्य होगा।

सम्पदा अधिकारी

हुडा.....

- नोट.—**
1. यदि आबंटिती कोई अटार्नी नियुक्त करता है, तो वह पंजीकृत/पावती डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप में विलेख के पंजीकरण से एक सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सांक्ष्याकित आबंटिती तथा अटार्नी के फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ पंजीकृत अटार्नी की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करेगा/करेगी।
 2. पते में कोई परिवर्तन पंजीकृत पावती डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप में एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को सूचित करना चाहिए।
 3. आपसे इस कार्यालय के रिकार्ड के लिए एक सप्ताह के भीतर कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सांक्ष्याकित तीन नमूना हस्ताक्षरों का शपथ-पत्र तथा एक स्टैम्प आकार का फोटो प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।
 4. आपसे सभी आबंटितियों की वैवाहिक स्थिति अर्थात् विवाहित/अविवाहित/एकल/विधवा की स्थिति भी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। विधवा के मामले में, पति/पत्नी की मृत्यु की तिथि सूचित की जाए।

पंजीकृत

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

सम्पदा कार्यालय

प्रारूप "सी.सी.बी."

(देखिये विनियम 6 (2))

(बूथों/कियोस्कों के लिए ई-नीलामी के माध्यम से पूर्ण स्वामित्व आधार पर किए गए आबंटन के लिए आबंटन पत्र का प्रारूप)

सेवा में

.....

.....

.....

आबंटियों की
तस्वीर

यादि क्रमांक : ई.ओ. () /

दिनांक

विषय :- पूर्ण स्वामित्व आधार पर शहरी सम्पदा के सैक्टर में स्थित बूथ/कियोस्क स्थल/भवन संख्या का बिक्री द्वारा आबंटन।

यह जैसा है जहां है के आधार पर शहरी सम्पदा के सैक्टर में स्थल/भवन नम्बर के लिए आपकी बोली के संदर्भ में है।

2. शहरी सम्पदा के सैक्टर में प्लॉट/भवन नम्बर के लिए आप की बोली स्वीकृत कर ली गई है तथा प्लॉट/भवन जिसके ब्योरे नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार तथा हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (जिसे, इसमें, इसके बाद अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) तथा उसके अधीन लागू तथा समय समय पर यथा संशोधित नियमों/विनियमों/संहिता/हिदायतों/मार्गदर्शनों के उपबन्धों के अधीन जिसमें नीलामी के समय पर पहले ही घोषित निबन्धनों तथा शर्तें शामिल हैं तथा आप द्वारा स्वीकृत की गई है, के अनुसार पूर्ण स्वामित्व आधार पर आप को आबंटित किया गया है :-

सैक्टर नम्बर	शहरी सम्पदा का नाम	प्लॉट/ भवन नम्बर	नीलामी के समय पर यथा अधिसूचित लगभग परिमाण या वर्णन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	कीमत (रुपए में)

3. बोली राशि के 10 % के लिए आप द्वारा जमा रु0 की राशि प्लॉट/भवन की कीमत के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।
4. इसके अतिरिक्त, आप से नीलामी की तिथि से 45 दिन की अवधि के भीतर आप द्वारा पहले ही भुगतान राशि सहित उक्त प्लॉट/भवन की कुल बोली कीमत का 40 % होगा/— रुपए जमा कराने का अनुरोध किया जाता है। उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त राशि जमा कराने में असफल होने के मामले में, आबंटन रद्द कर दिया जाएगा तथा बोली के समय पर जमा की गई 10 % बोली राशि प्राधिकरण में जब्त हो जाएगी जिसके विरुद्ध आपका हानियों के लिए कोई दावा नहीं होगा।
5. उसके पश्चात, उक्त प्लॉट/भवन की बोली राशि की बाकी की 60 % राशि अर्थात् रुपए नीलामी की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर बिना ब्याज के एकमुश्त या छह अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतान की जाएगी। पहली किस्त नीलामी की तिथि से छह मास की समाप्ति के बाद देय होगी। प्रत्येक किस्त इस आबंटन पत्र के खण्ड नम्बर 29 में यथा वर्णित शेष राशि पर 9 % प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वसूलीयोग्य होगी। तथापि, यदि, कुल बोली राशि की बकाया 60 % राशि नीलामी की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर एकमुश्त भुगतान की जाती है, तो कुल कीमत में 5 % की छूट अनुज्ञात होगी।
6. आपको प्लॉट/भवन का कब्जा इसके द्वारा दिया जाता है, जोकि उपरोक्त क्रम संख्या-4 में मांगे गये अनुसार बकाया 30 % राशि का भुगतान करने के बाद तुरन्त लिया जा सकता है, जैसा कि क्षेत्र में विकास कार्य (मूल

- सुखसुविधाएं) पहले ही पूरे कर दिये गये हैं। इस प्रयोजन के लिए विकास कार्यों का अर्थ मूल सुखविधाओं अर्थात् डब्ल्यूबीएम स्तर तक सड़क, पानी, बिजली तथा सीवरेज की व्यवस्था होगी।
7. पूर्वोक्त अदायगी के भुगतान के लिए अलग से कोई भी नोटिस नहीं भेजा जाएगा।
 8. सभी भुगतान/किस्तें हुडा वैबसाईट पर आनलाईन भुगतान द्वारा या हुडा वैबसाईट पर पीपीएम प्रणाली से चालान उत्पन्न करके प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से ऑफ लाईन पद्धति के द्वारा भुगतान की जाएंगी। देय तिथि तक किस्त (किस्तों) का भुगतान अनिवार्य है। यदि देय तिथि तक किस्त (किस्तों) का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आप विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस समय, किस्त के विलम्बित भुगतान पर ब्याज साधारण ब्याज आधार पर 12 % प्रति वर्ष की दर से भुगतान योग्य है। भविष्य में सफल बोलीदाता को किस्तों के विलम्बित भुगतान पर ब्याज साधारण या चक्रवृति तथा ऐसी दर पर जो इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि क्या कब्जा दिया गया है या नहीं तथा अधिनियम की धारा 17 के अधीन कार्यवाही करने के लिए प्राधिकरण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निश्चित किया जाये, भुगतान करना होगा।
 9. यदि किस्त देय तिथि तक भुगतान नहीं की जाती है, तो सम्पदा अधिकारी अधिनियम की धारा 17 के उपबन्धों के अनुसार शास्ति के अधिरोपण तथा प्लॉट के पुनः ग्रहण के लिए कार्यवाही करने हेतु अग्रसर होगा।
 10. जब कभी यदि आप निर्माण से पहले किसी समय पर स्थल समर्पित करते हैं, तो सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी, हुडा ऐसे समर्पण के आवेदन की तिथि तक देय ब्याज तथा शास्ति, यदि कोई हो, सहित कुल प्रतिफल धन राशि का 10% काटने के बाद राशि वापस करेगा। तथापि, कोई भी ब्याज वापस की जाने वाली ऐसी राशि पर भुगतानयोग्य नहीं होगा।
 11. समर्पण के लिए निवेदन हुडा द्वारा आबंटित लागईन आई डी तथा पासवर्ड का प्रयोग करते हुए हुडा वैबसाईट पर पीपीएम प्रणाली पर आनलाईन प्रस्तुत किया जाना है। किसी अन्य रीति से अर्पण स्वीकार्य नहीं होगा।
 12. तथापि, यदि न्यायालय द्वारा स्थगन या वाद या हुडा के नियन्त्रण से बाहर किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण, हुडा सम्पूर्ण बोली राशि तथा ब्याज जमा कराने के बाद तीन मास के भीतर प्लॉट/स्थल का कब्जा देने में योग्य नहीं है, तो आप द्वारा जमा सम्पूर्ण राशि केवल आप द्वारा भुगतान की गई, बोली राशि पर संगणित किये जाने वाले 5.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित वापस लौटाई जाएगी। आप का इस स्थल/स्थलों या किसी दूसरे वैकल्पिक स्थल/स्थलों पर कोई दावा नहीं होगा।
 13. किसी शर्त के उल्लंघन की घटना में, सम्पदा अधिकारी, हुडा अधिनियम की धारा 17 के उपबन्धों के अनुसार स्थल पुनः ग्रहण कर सकता है तथा जमा की गई राशि कुल प्रतिफल राशि का 10 %, पुनः ग्रहण की तिथि तक भुगतानयोग्य ब्याज तथा अन्य देयों को जब्त करने के बाद वापस लौटाई जाएगी। वापस की जाने वाली ऐसी राशि पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा।
 14. पुनः ग्रहण के बाद, आप अपनी स्वयं की लागत पर पुनः ग्रहण आदेश की तीन मास की अवधि के भीतर संरचना/मलबा/फिक्सचर, यदि कोई हो, हटाने के लिए स्वतन्त्र होंगे, जिसमें असफल होने पर आप की लागत पर हुडा द्वारा हटवाया जाएगा।
 15. स्थल, स्थल की बिक्री के कारण हुडा को देय ब्याज तथा अन्य राशि सहित सम्पूर्ण बोली धन राशि का भुगतान करने तक तथा आप के पक्ष में हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करने तक नियंत्रण हुडा के पास रहेगा। आप को हस्तान्तरण विलेख के निष्पादन के बाद भी सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी, हुडा की पूर्व लिखित अनुमति के बिना स्थल का अन्तरण करने तथा उस पर कोई अधिकार/हक/हित सृजित करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तथापि, आप केवल प्लॉट के देयों इत्यादि सहित कीमत के भुगतान के लिए प्लॉट के विरुद्ध कर्ज राशि प्राप्त करने के लिए स्थल को गिरवी रख सकते हैं या उस पर कोई अधिकार/हित सृजित कर सकते हैं किन्तु सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी, हुडा की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी।
 16. बोली राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, इत्यादि के शत प्रतिशत भुगतान पर, आप निर्धारित प्ररूप में तथा ऐसी रीति में, जैसा सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी, हुडा द्वारा निदेशित किया जाए, अपने पक्ष में हस्तान्तरण विलेख तैयार कराएंगे। हस्तान्तरण विलेख प्लॉट/भवन की सम्पूर्ण कीमत का भुगतान करने के एक वर्ष के भीतर निष्पादित किया जाएगा। तथापि, इसमें विनिर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि में हस्तान्तरण विलेख का इस प्रकार निष्पादन करने में असफल रहने के मामले में, हस्तान्तरण विलेख इसके निष्पादन के वर्ष में अभिभावी कलक्टर दरों पर या नीलामी कीमत, जो भी अधिक हो, संगणित स्थल के मूल्य पर स्टाम्प शुल्क पर निष्पादनयोग्य होगा। पंजीकरण तथा स्टाम्प शुल्क के प्रभार सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किए जाएंगे।
 17. नीलामी स्थल पर भवन के निर्माण के लिए शर्तें स्थल की जोनिंग प्लान या स्थल के "मानक डिजाइन" तथा समय-समय पर बनाई गई तथा संशोधित की गई हरियाणा भवन संहिता, 2016 के अनुसार शासित होंगी। भवन सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी, हुडा से नक्शा स्वीकृत कराने के बाद निर्मित किया जाएगा। आप सम्पदा अधिकारी की पूर्व/सुस्पष्ट लिखित अनुमति के बिना स्थल पर निर्मित ढांचे में कोई परिवर्तन/परिवर्धन नहीं करेंगे।

18. बूथ/कियोस्क के स्थल के सामने विस्तार (रास्ता/बरामदा) आम रास्ते से अन्यथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
19. आप को भवन के निर्माण को शासित करने वाले नियमों/विनियमों/संहिता के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्रस्तावित भवन का नक्शा स्वीकृत कराने के बाद कब्जा देने की तिथि के दो वर्ष के भीतर निर्माण पूरा करना होगा। समय सीमा समय-समय पर हुडा द्वारा यथा निर्धारित विस्तार फीस के भुगतान की शर्त के अधीन सम्पदा अधिकारी द्वारा विस्तारयोग्य है, अन्यथा यह प्लॉट पुनः ग्रहण किए जाने के लिए उत्तरदायी है तथा इसके सम्बन्ध में भुगतान की गई सम्पूर्ण धनराशि या उसका भाग, यदि कोई हो, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी है। आप सम्पदा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भवन का निर्माण या कोई परिवर्तन/परिवर्धन नहीं करेंगे।
20. स्थल/भवन का प्रयोग उस प्रयोजन जिस के लिए यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुसार आबंटित किया गया है, से अन्यथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। भूमि/भवन में या पर कोई भी आपतिजनक (हानिकर) व्यापार नहीं किया जाएगा।

स्थल को किन्हीं भी परिस्थितियों में उप विभाजित या विखण्डित नहीं किया जाएगा।

21. आप को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कथित भूमि/भवन पर अधिरोजित या निर्धारित सभी साधारण तथा स्थानीय करों, दरों या उप करों का भुगतान करना होगा।
22. आप को आबंटन के समय पर आप के प्लॉट में विद्यमान किसी निर्माण सामग्री, ईंट, संरचना तथा कम्पाउंड दीवार इत्यादि का अलग से भुगतान करना होगा जिस का मुआवजा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तथा भुगतान किया गया है, यदि आप उसका प्रयोग करना चाहते हैं।

प्राधिकरण असमतल स्थलों को समतल करने के लिए जिम्मेवार नहीं होगा क्योंकि स्थल "जैसा है जहां है आधार पर" नीलाम किंग गए हैं।

23. प्राधिकरण ऐसे सभी अधिकारों तथा शक्तियों सहित कथित स्थल में या के नीचे सभी खान तथा खनिज जो भी हों, को स्वयं आरक्षित रखता है जो कथित स्थल के सभी या किसी भाग की किसी सतह या कोई भूमिगत कार्य करने तथा सतह से निकालने तथा ऐसी सभी बातों को करने के प्रयोजन के लिए कथित स्थल पर गड़ढ़े खोदने, भवन बनाने, लाईनों का निर्माण करने तथा सामान्यतः उचित तथा सही प्रयोग करने की शक्ति सहित ऐसी रीति में ऐसे सभी समयों पर उसकी छानबीन करने, कार्य करने, प्राप्त करने, हटाने तथा उपभोग करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा समीचीन हो जो प्राधिकरण उचित समझे जो उसमें दिए गए उपवादों तथा आरक्षणों के सम्पूर्ण उपयोग के लिए सुविधाजनक या आवश्यक हो:

परन्तु आप सतह का प्राधिकरण द्वारा अधिभोग के लिए तथा आप तथा प्राधिकरण के बीच किए गए करार के अनुसार ऐसे कार्यों या कार्य करने या भाड़े पर देने से कथित भूमि की सतह या भावन को की गई हानि के लिए ऐसे भुगतान प्राधिकरण से प्राप्त करने का हकदार होंगे या ऐसे करार में असफल होने पर जैसा माध्यस्थ के निर्देश से पता लगाया जाएगा।

24. प्राधिकरण यह पता लगाने के प्रयोजन के लिए कि आपने उक्त अधिनियम के अधीन लागू नियम/संहिता/विनियमों के अधीन पालन की जाने वाली शर्तों को विधिवत पूरा तथा पालन किया है, कथित भूमि/उस पर निर्मित भवन में या उसके किसी भाग पर लिखित में 24 घण्टे के बाद सभी युक्तियुक्त समयों पर तथा युक्तियुक्त रीति में अपने अधिकारियों तथा नौकरों द्वारा प्रवेश कर सकता है।
25. प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या नौकरों के माध्यम से सभी कार्य तथा बातें करने के लिए सभी समयों पर पूरे अधिकार शक्ति तथा प्राधिकार होगा जो अधिरोपित सभी या किन्हीं निबन्धनों, शर्तों तथा आरक्षणों को लागू करने, अनुपालन तथा कथित भूमि/भवन पर प्रथम प्रभार, ऐसे सभी या कोई कार्य तथा बातें करने की लागत तथा उसके सम्बन्ध में या उसमें तथा उसमें सम्बन्धित किसी रूप में उपगत सभी लागतों के रूप में आप से वसूल करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो।
26. इस आबंटन के विषय में या के सम्बन्ध में या किसी रूप में किसी भी प्रकार से उत्पन्न सभी विवाद तथा झगड़े मुख्य प्रशासक के एक मात्र मध्यस्थता या उस द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को निर्दिष्ट किए जाएंगे। ऐसी नियुक्ति के लिए कोई आक्षेप नहीं होगा कि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ सरकारी कर्मचारी है या प्राधिकरण को कोई अधिकारी है कि उसने मामले का निदान किया था। जिससे यह आबंटन ऐसे सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में उसकी ड्यूटी के सिलसिले में सम्बन्धित है, उसने विवाद या झगड़े में सभी या किन्हीं विषयों में अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा तथा सम्बन्धित पक्षकारों पर बाध्य होगा।

27. अर्धवार्षिक किस्तें प्रत्येक वर्ष की दिनांकतथाको देय होंगी।
अर्धवार्षिक किस्तों के ब्योरे निम्नानुसार है:-

किस्त नं०	मूल (रुपये में)	ब्याज (रुपये में)	कुल (रुपये में)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

सम्पदा अधिकारी

हुडा,.....

नोट :

- यदि आबंटिती कोई अटार्नी नियुक्त करता है, तो वह पंजीकृत/पावती डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप में विलेख के पंजीकरण से एक सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सांक्ष्याकित आबंटिती तथा अटार्नी के फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ पंजीकृत अटार्नी की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करेगा/करेगी।
- पते में कोई परिवर्तन पंजीकृत पावती डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप में एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को सूचित करना चाहिए।
- आपसे इस कार्यालय के रिकार्ड के लिए एक सप्ताह के भीतर कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सांक्ष्याकित तीन नमूना हस्ताक्षरों का शपथ-पत्र तथा एक स्टैम्प आकार का फोटो प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।
- आपसे सभी आबंटितियों की वैवाहिक स्थिति अर्थात् विवाहित/अविवाहित/एकल/विधवा की स्थिति भी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। विधवा के मामले में, पति/पत्नी की मृत्यु की तिथि सूचित की जाए।

पंजीकृत

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

सम्पदा कार्यालय

प्रारूप "सी.सी.जी."

(देखिये विनियम 6 (2))

(अधिमान्य (जी.पी./पी./एस.पी.) रिहायशी/संस्थागत/वाणिज्यिक स्थल/भवन के लिए ई-नीलामी के माध्यम से पूर्ण स्वामित्व आधार पर किए गए आबंटन के लिए आबंटन पत्र का प्रारूप)

सेवा में

.....

यादि क्रमांक : ई.ओ. () /

दिनांक

आबंटियों की
तस्वीर

विषय :-

पूर्ण स्वामित्व आधार पर शहरी सम्पदा के सैक्टर में अधिमान्य (जी.पी./पी./एस.पी.) रिहायशी प्लॉट/संस्थागत/वाणिज्यिक स्थल/भवन संख्या की बिक्री द्वारा आबंटन।

यह जैसा है जहां है के आधार पर नीलाम शहरी सम्पदा के सैक्टर में स्थल/भवन नम्बर के लिए आपकी बोली के संदर्भ में है।

2. शहरी सम्पदा के सैक्टर में प्लॉट/भवन नम्बर के लिए आप की बोली स्वीकृत कर ली गई है तथा प्लॉट/भवन जिसके ब्योरे नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार तथा हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (जिसे, इसमें, इसके बाद अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) तथा उसके अधीन लागू तथा समय समय पर यथा संशोधित नियमों/विनियमों/संहिता/हिदायतों/मार्ग दर्शनों के उपबन्धों के अधीन जिसमें नीलामी के समय पर पहले ही घोषित निबन्धनों तथा शर्तें शामिल हैं तथा आप द्वारा स्वीकृत की गई है, के अनुसार पूर्ण स्वामित्व आधार पर आप को आबंटित किया गया है :-

सैक्टर नम्बर	शहरी सम्पदा का नाम	प्लॉट/ भवन नम्बर	नीलामी के समय पर यथा अधिसूचित लगभग परिमाण या वर्णन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	कीमत (रुपए में)

3. बोली राशि के लिए आप द्वारा जमा रु० की राशि प्लॉट/भवन की कीमत के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।
4. इसके अतिरिक्त, आप से नीलामी की तिथि से 45 दिन की अवधि के भीतर अर्थात् (.....तक) आप द्वारा पहले ही भुगतान की गई राशि के साथ उक्त प्लॉट/भवन की कुल बोली कीमत का 25 % होगा, जमा कराने का अनुरोध किया जाता है। उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त राशि जमा कराने में असफल होने के मामले में, आबंटन रद्द कर दिया जाएगा तथा बोली के समय पर जमा की गई 10 % बोली राशि प्राधिकरण में जब्त हो जाएगी जिसके विरुद्ध आपका हानियों के लिए कोई दावा नहीं होगा।
5. उसके पश्चात, उपरोक्त प्लॉट/भवन की कुल बोली राशि की बाकी की 75 % राशि अर्थात्/— रुपए नीलामी तिथि से 120 दिन (रिहायशी प्लॉट के लिए) या 180 दिन (अन्य प्रवर्गों के लिए) के भीतर बिना ब्याज के एकमुश्त भुगतान की जाएगी, जिसमें असफल होने पर यह आबंटन बिना किसी नोटिस के रद्द हो जाएगा तथा आप द्वारा जमा बोली राशि का 25 % जब्त हो जाएगी तथा आप का हानि के लिए कोई भी दावा नहीं होगा।

6. पूर्वोक्त अदायगी के भुगतान के लिए अलग से कोई भी नोटिस नहीं भेजा जाएगा।
7. सभी भुगतान या तो हुडा वैबसाईट पर आनलाईन पद्धति के द्वारा या हुडा वैबसाईट पर चालान उत्पन्न करके प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से ऑफ लाईन पद्धति से किया जाएगा।
8. जब कभी यदि आप नीलामी की तिथि से 120 दिन (रिहायशी प्लॉट के लिए) या 180 दिन (अन्य प्रवर्गों के लिए) की अवधि के भीतर किसी समय पर स्थल समर्पित करते हैं, तो सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी, हुडा ऐसे समर्पण के आवेदन की तिथि तक देय ब्याज तथा शास्ति, यदि कोई हो, सहित कुल प्रतिफल धन राशि का 10 % काटने के बाद राशि वापस करेगा। तथापि, वापस की जाने वाली ऐसी राशि पर कोई भी ब्याज भुगतानयोग्य नहीं होगा।
9. समर्पण के लिए निवेदन हुडा द्वारा आर्बिट्रिट लागर्न आई डी तथा पासवर्ड का प्रयोग करते हुए हुडा वैबसाईट पर पीपीएम प्रणाली पर आनलाईन प्रस्तुत किया जाना है। किसी अन्य तरीके से समर्पण स्वीकार्य नहीं होगा।
10. स्थल/प्लॉट का कब्जा आप द्वारा हुडा में केवल सम्पूर्ण बोली राशि का भुगतान करने के बाद ही दिया जाएगा। यदि प्लॉट का कब्जा सम्पूर्ण बोली राशि के जमा करने के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर नहीं दिया गया है, तो हुडा कब्जा देने की तिथि तक आप द्वारा जमा राशि पर 5.5 % प्रतिवर्ष (या जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए) की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। तथापि, ऐसा ब्याज यथा पूर्वोक्त 30 दिन की समाप्ति के बाद तथा कब्जा देने की तिथि तक संगणित अवधि के लिए भुगतानयोग्य होगा।
11. तथापि, यदि न्यायालय द्वारा स्थगन या वाद या हुडा के नियन्त्रण से बाहर किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण, हुडा सम्पूर्ण (100 %) बोली राशि जमा कराने के बाद तीन मास के भीतर प्लॉट/स्थल का कब्जा देने में योग्य नहीं है, तो आप द्वारा जमा सम्पूर्ण राशि वापस लौटाई जाएगी। आप का इस स्थल/स्थलों या किसी दूसरे वैकल्पिक स्थल/स्थलों पर कोई दावा नहीं होगा।
12. किसी शर्त के उल्लंघन की घटना में, सम्पदा अधिकारी, हुडा अधिनियम की धारा 17 के उपबन्धों के अनुसार स्थल पुनः ग्रहण कर सकता है तथा जमा की गई राशि कुल प्रतिफल राशि का 10 %, पुनः ग्रहण की तिथि तक भुगतानयोग्य ब्याज तथा अन्य देयों को जब्त करने के बाद वापस लौटाई जाएगी। वापस की जाने वाली ऐसी राशि पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा।
13. पुनः ग्रहण के बाद, आप अपनी स्वयं की लागत पर पुनःग्रहण आदेश की तीन मास की अवधि के भीतर संरचना/मलबा/फिक्सचर, यदि कोई हो, हटाने के लिए स्वतन्त्र होंगे, जिसमें असफल होने पर आप की लागत पर हुडा द्वारा हटवाया जाएगा।
14. स्थल, स्थल की बिक्री के कारण हुडा को देय ब्याज तथा अन्य राशि सहित सम्पूर्ण बोली धन राशि का भुगतान करने तक तथा आप के पक्ष में हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करने तक नियंत्रण हुडा के पास रहेगा। आप को हस्तान्तरण विलेख के निष्पादन के बाद भी सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी, हुडा की पूर्व लिखित अनुमति के बिना स्थल का अन्तरण करने तथा उस पर कोई अधिकार/हक/हित सृजित करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तथापि, आप केवल प्लॉट के देयों इत्यादि सहित कीमत के भुगतान के लिए प्लॉट के विरुद्ध कर्ज राशि प्राप्त करने के लिए स्थल को गिरवी रख सकते हैं या उस पर कोई अधिकार/हित सृजित कर सकते हैं किन्तु सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी, हुडा की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी।
15. बोली राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, इत्यादि के शत प्रतिशत भुगतान पर, आप निर्धारित प्ररूप में तथा ऐसी शीति में, जैसा सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी, हुडा द्वारा निदेशित किया जाए, अपने पक्ष में हस्तान्तरण विलेख तैयार कराएंगे। हस्तांतरण विलेख प्लॉट/भवन को सम्पूर्ण कीमत का भुगतान करने के एक वर्ष के भीतर निष्पादित किया जाएगा। तथापि, इसमें विनिर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि में हस्तान्तरण विलेख का इस प्रकार निष्पादन करने में असफल रहने के मामले में, हस्तान्तरण विलेख इसके निष्पादन के वर्ष में अभिभावी कलक्टर दरों पर या नीलामी कीमत, जो भी अधिक हो, संगणित स्थल के मूल्य पर स्टाम्प शुल्क पर निष्पादनयोग्य होगा। पंजीकरण तथा स्टाम्प शुल्क के प्रभार आप द्वारा भुगतान किए जाएंगे।
16. स्थल का प्रयोग उस प्रयोजन जिस के लिए यह आर्बिट्रिट किया गया है, से अन्यथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। स्थल पर कोई भी आपतिजनक (हानिकर) कार्यकलाप नहीं किया जाएगा। तथापि, केवल रिहायशी प्लॉटों के मामले में हुडा विनियम, 1978 तथा इसके अधीन जारी की गई तथा समय-समय पर संशोधित पालिसी के अनुसार, गैर-उपद्रव व्यावसायिक परामर्शी सेवाएं अनुमत हैं।
17. स्थल को किन्हीं भी परिस्थितियों में उप विभाजित या विखण्डित नहीं किया जाएगा। तथापि, केवल रिहायशी प्लॉटों के मामले में पालिसी के अनुसार स्वतन्त्र मंजिलों का पंजीकरण पालिसी के अनुसार अनुमति है।
18. आप को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कथित भूमि/भवन पर अधिरोपित या निर्धारित सभी साधारण तथा स्थानीय करों, दरों या उप करों का भुगतान करना होगा।

19. आप को आबंटन के समय पर आप के प्लॉट में विद्यमान किसी निर्माण सामग्री, ईट, संरचना तथा कम्पाउंड दीवार इत्यादि का अलग से भुगतान करना होगा जिस का मुआवजा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तथा भुगतान किया गया है। यदि आप उसका प्रयोग करना चाहते हैं।
 20. प्राधिकरण असमतल स्थलों को समतल करने के लिए जिम्मेवार नहीं होगा तथा स्थल जैसा है जहां है आधार पर नीलाम किया गया है।
 21. नीलाम स्थल पर भवन के निर्माण के लिए शर्तें, स्थल की जोनिंग प्लान तथा वाणिज्यिक स्थल के मामले में "मानक डिजाईन" द्वारा भी; समय-समय पर बनाई गई तथा संशोधित हरियाणा भवन संहिता, 2016 के अनुसार शासित होंगी। भवन सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी, हुड्डा से नक्शा स्वीकृत कराने के बाद निर्मित किया जाएगा। आप सम्पदा अधिकारी की पूर्व/सुस्पष्ट लिखित अनुमति के बिना स्थल पर निर्मित ढांचे में कोई परिवर्तन/परिवर्धन नहीं करेंगे।
 22. वाणिज्यिक स्थलों के मामले में, दुकान एवं फ्लैट/दुकान एवं कार्यालय इत्यादि के स्थल के सामने का विस्तार (रास्ता/बरामदा) आम रास्ते से अन्यथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा।
 23. आप को भवन के निर्माण को शासित करने वाले विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्रस्तावित भवन का नक्शा स्वीकृत कराने के बाद कब्जा देने की तिथि के दो वर्ष के भीतर निर्माण पूरा करना होगा। समय सीमा समय-समय पर हुड्डा द्वारा यथा निर्धारित विस्तार फीस के भुगतान की शर्त के अधीन सम्पदा अधिकारी द्वारा विस्तारयोग्य है, अन्यथा यह प्लॉट पुनः ग्रहण किए जाने के लिए उत्तरदायी है तथा इसके सम्बन्ध में भुगतान की गई सम्पूर्ण धनराशि या उसका भाग, यदि कोई हो, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी है। आप सम्पदा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भवन का निर्माण या कोई परिवर्तन/परिवर्धन नहीं करेंगे।
 24. प्राधिकरण ऐसे सभी अधिकारों तथा शक्तियों सहित कथित स्थल में या के नीचे सभी खान तथा खनिज जो भी हों, को स्वयं आरक्षित रखता है जो कथित स्थल के सभी या किसी भाग की किसी सतह या कोई भूमिगत कार्य करने तथा सतह से निकालने तथा ऐसी सभी बातों को करने के प्रयोजन के लिए कथित स्थल पर गड़ढ़े खोदने, भवन बनाने, लाईनों का निर्माण करने तथा सामान्यतः उचित तथा सही प्रयोग करने की शक्ति सहित ऐसी रीति में ऐसे सभी समयों पर उसकी छानबीन करने, कार्य करने, प्राप्त करने, हटाने तथा उपभोग करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा समीचीन हो जो प्राधिकरण उचित समझे जो उसमें दिए गए अपवादों तथा आरक्षणों के सम्पूर्ण उपभोग के लिए सुविधाजनक या आवश्यक हो :
- परन्तु आप सतह का प्राधिकरण द्वारा अधिभोग के लिए तथा आप तथा प्राधिकरण के बीच किए गए करार के अनुसार ऐसे कार्यों या कार्य करने या भाड़े पर देने से कथित भूमि की सतह या भवन को की गई हानि के लिए ऐसे भुगतान प्राधिकरण से प्राप्त करने का हकदार होंगे या ऐसे करार में असफल होने पर जैसा माध्यस्थ के निर्देश से पता लगाया जाएगा।
25. प्राधिकरण यह पता लगाने के प्रयोजन के लिए कि आबंटिती उक्त अधिनियम के अधीन लागू नियम/संहिता/विनियमों के अधीन पालन की जाने वाली शर्तों को विधिवत पूरा तथा पालन करता है, कथित भूमि/उस पर निर्मित भवन में या उसके किसी भाग पर लिखित में 24 घण्टे के बाद सभी युक्तियुक्त समयों पर तथा युक्तियुक्त रीति में अपने अधिकारियों तथा नौकरों द्वारा प्रवेश कर सकता है।
 26. प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या नौकरों के माध्यम से सभी कार्य तथा बातें करने के लिए सभी समयों पर पूरे अधिकार, शक्ति तथा प्राधिकार होगा जो अधिरोपित सभी या किन्हीं निबन्धनों, शर्तों तथा आरक्षणों को लागू करने, अनुपालन तथा कथित भूमि/भवन पर प्रथम प्रभार, ऐसे सभी या कोई कार्य तथा बातें करने की लागत तथा उसके सम्बन्ध में या उसमें तथा उसमें सम्बन्धित किसी रूप में उपगत सभी लागतों के रूप में आप से वसूल करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो।
 27. इस आबंटन के विषय में या के सम्बन्ध में या किसी रूप में किसी भी प्रकार से उत्पन्न सभी विवाद तथा झगड़े मुख्य प्रशासक के एक मात्र मध्यस्थता या उस द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को निर्दिष्ट किए जाएंगे। ऐसी नियुक्ति के लिए कोई आक्षेप नहीं होगा कि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ सरकारी कर्मचारी है या प्राधिकरण को कोई अधिकारी है कि उसने मामले का निपटान किया था जिससे यह आबंटन ऐसे सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में उसकी ड्यूटी के सिलसिले में सम्बन्धित है, उसने विवाद या झगड़े में सभी या किन्हीं विषयों में अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा तथा सम्बन्धित पक्षकारों पर बाध्य होगा।

सम्पदा अधिकारी
हुड्डा

नोट :

1. यदि आबंटिती कोई अटार्नी नियुक्त करता है, तो वह पंजीकृत/पावती डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप में विलेख के पंजीकरण से एक सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सांक्ष्यिकित आबंटिती तथा अटार्नी के फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ पंजीकृत अटार्नी की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करेगा/करेगी।
2. पते में कोई परिवर्तन पंजीकृत पावती डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप में एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को सूचित करना चाहिए।
3. आपसे इस कार्यालय के रिकार्ड के लिए एक सप्ताह के भीतर कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सांक्ष्यिकित तीन नमूना हस्ताक्षरों का शपथ-पत्र तथा एक स्टैम्प आकार का फोटो प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।
4. आपसे सभी आबंटितियों की वैवाहिक स्थिति अर्थात् विवाहित/अविवाहित/एकल/विधवा की स्थिति भी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। विधवा के मामले में, पति/पत्नी की मृत्यु की तिथि सूचित की जाए।

HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY

Notification

The 20th May, 2017

No. Auth. 83286.— In exercise of powers conferred by clause (e) of Section 54 of the Haryana Urban Development Authority Act, 1977 (Act 13 of 1977) and with the previous approval of the State Government, conveyed *vide* memo No. 7/2/2017-2TCP dated 11-4-2017, the Haryana Urban Development Authority hereby makes the following regulation further to amend the Haryana Urban Development Authority (disposal of Land and Buildings) Regulations, 1978 namely:—

1. These regulations may be called the Haryana Urban Development Authority (Disposal of Land Buildings) Amendment Regulations, 2017.
2. In the Haryana Urban Development Authority (Disposal of Land and Buildings) Regulations, 1978, Sub Regulation (2) of the Regulation 6 shall be substituted with the following provision:
“The payment shall be made by the highest bidder as per terms and conditions notified for e-auction failing which amount already deposited shall stand forfeited to the Authority and successful bidder shall have no claim to the Land or Building auctioned. The successful bidder shall be issued allotment letter in the format of ‘CC-R’, ‘CC-B’ and ‘CC-G’”.
3. Format of form ‘CC-R’, ‘CC-B’ and ‘CC-G’ is as annexed.

VIKAS GUPTA,
Chief Administrator
Haryana Urban Development Authority.

Registered

HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY

Estate Officer, _____.

FORM "CC-R"

(See Regulation-6 (2))

(Form of Allotment letter, for allotment made on free-hold basis –through e-auction for left out resident plots)

PHOTOGRAPH OF ALLOTTEE(S)

To

Memo No. : EO()/

Dated _____

Subject: Allotment by sale of left out residential plots site/building No. ____ in Sector- _____, Urban Estate _____ on free hold basis.

Please refer to your bid for site/building No. _____ in Sector _____ at _____ auctioned on as is where is basis.

2. Your bid for plot/building No. ____ in Sector _____ Urban Estate _____ has been accepted and the plot/building as detailed below, has been allotted to you on free hold basis as per the following terms and conditions and subject to the provisions of the Haryana Urban Development Authority Act, 1977 (hereinafter referred to as the Act) and the Rules/ Regulations/ code/ instructions/guidelines applicable thereunder and as amended from time to time including terms and conditions as already announced at the time of auction and accepted by you.

Sector No.	Name of Urban Estate	Plot/ building No.	Approximate dimension or description as notified at the time of auction	Area (In sq.mtr.)	Price (in ₹.)

3. The sum of ₹. ____/- deposited by you towards bid amount will be adjusted against the price of the plot/building.
4. Further you are requested to remit ₹. ____/- within 45 days (upto ____) from the date of auction, which together with the amount already paid by you, will constitute 25% of the total bid price of said plot/building. In case of failure to deposit the said amount within the above specified period, the allotment shall be cancelled and the 10% bid money deposited at the time of bid shall stand forfeited to the Authority, against which you shall have no claim for damages.
5. Thereafter, remaining 75% amount of the total bid amount i.e ₹. ____/- of the above plot/building shall be paid in lumpsum within 120 days from the date of auction without interest, failing

- which this allotment shall stand cancelled without any notice and 25% bid money deposited by you shall forfeited and you shall have no claim for the damages.
6. No separate notice will be sent for payment of the aforesaid payments.
 7. All payments shall be made either through online mode on HUDA Website or off line mode through authorized Banks by generating challan from PPM on the HUDA website.
 8. Wherever in case you surrender the site at any time within a period of 120 days from auction, the concerned Estate Officer, HUDA will refund the amount after deducting 10% of the total consideration money including interest and penalty if any due upto the date of application for such surrender. However, no interest shall be payable on such amount to be refunded.
 9. The request for surrender has to be submitted online on the PPM module on HUDA Website by using the login id and password allotted by HUDA. Surrender by any other mode shall not be acceptable.
 10. The possession of the site/plot shall be offered only after full bid amount has been paid to HUDA by you. In case possession of the plot is not offered within 30 days after deposit of full bid amount, HUDA will pay interest @ 5.5 % P.A. (or as may be fixed by Authority from time to time) on the amount deposited by you till the date of offer of possession. However such interest shall be payable for the period calculated after expiry of 30 days as aforesaid and till the date of offer of possession.
 11. However, if due to stay by the Court or litigation or any other circumstances beyond its control, HUDA is not able to offer possession of the plot/site within three months after deposit of full (100%) highest bid amount, the full amount deposited by you shall be refunded back you, will not have any claim, on this site/sites, or any other site/ sites.
 12. In the event of breach of any condition, the concerned Estate Officer, HUDA may resume the site in accordance with the provisions of sector 17 of the HUDA Act, 1977 and the money deposited shall be refunded back after deducting 10% of the total consideration money, interest and other dues payable upto the date of resumption. No interest shall be paid on such amount to be refunded.
 13. Upon resumption, you will be free to remove the structure/debris/fixtures, if any, within a period of three months of resumption order at his own cost, failing which it shall be removed by the HUDA at your cost.
 14. The site shall continue to belong to HUDA until the entire bid money together with interest and other amount due to HUDA on account of sale of site is paid and deed of conveyance in your favour is executed. You shall have no right to transfer the site or create any right/title/interest thereon without prior written permission of the concerned Estate Officer, HUDA even after execution of Deed of Conveyance. You may however mortgage or create any right/interest on the site only to secure the loan amount against the plot towards payment of price including dues etc. of the plot but prior written permission of the concerned Estate Officer, HUDA shall be required.
 15. On payment of 100% of the bid amount and interest, if any, etc., you shall get the deed of conveyance executed in your favour in the prescribed form and in such manner as may be directed by the concerned Estate Officer, HUDA. The deed of conveyance shall be executed within one year of making payment of full price of the plot/ building. However, in case of failure to so execute the conveyance deed in one year period specified herein, the conveyance deed shall be executable on the stamp duty on value of site calculated at the prevailing collector rates prevailing in the year of its execution or auction price whichever is higher. The charges for the registration and stamp duty will be paid by you.
 16. The site shall not be used for any purpose other than that for which it has been allotted. No obnoxious activity shall be carried out on the site. However, as per HUDA Regulations, 1978 and policy issued there-under and amended from time to time, non nuisance professional consultancy services are permitted.
 17. The site shall not be subdivided or fragmented under any circumstances. However, registration of independent floors is permitted as per policy.
 18. You shall have to pay all general and local taxes, rates or cesses imposed or assessed on the said land/building by the competent authority.

19. You shall have to pay separately for any construction material, bricks, structures and compound wall etc. existing in your plot at the time of allotment of which compensation has been assessed and paid by the Authority, if you want to make use of the same.
20. The Authority shall not be responsible for leveling of uneven sites and the sites are being auctioned on as is where is basis.
21. The conditions for erection of building on the auctioned site shall be governed by the zoning plan of the site and in accordance with the Haryana Building Code, 2016 as framed and amended from time to time. The building shall be erected after getting the plans approved from the respective Estate Officer, HUDA. You shall not make any alterations/additions to the structure erected on the site without prior/explicit written permission of the Estate Officer.
22. This allotment shall be at the old FAR existing prior to implementation of Haryana Building Code, 2016 and additional FAR permissible under Haryana Building Code, 2016, shall have to be purchased separately by the allottee on payment of charges as approved by the Govt. from time to time.

Plot Size	Max. permissible coverage on each floor	FAR		
		Now being allotted	Additional Purchasable	Total
Upto 3-Marla	66	1.65	0.33	1.98
4-marla	66	1.65	0.33	1.98
6-Marla	66	1.45	0.53	1.98
8-Marla	66	1.45	0.53	1.98
10-marla	66	1.45	0.53	1.98
14-Marla	60	1.30	0.50	1.80
1-kanal	60	1.20	0.60	1.80
2-kanal	60	1.00	0.80	1.80

23. You will have to complete the construction within two years of the date of offer of possession after getting the plans of the proposed building approved from the competent authority in accordance with the regulations governing the erection of buildings. The time limit is extendable by the Estate Officer, subject to payment of extension fee as fixed by HUDA from time to time, otherwise this plot is liable to be resumed and the whole or part of the money paid, if any, in respect of it is liable to be forfeited in accordance with the provision of the Act. You shall not erect any building or make any alteration/addition without prior permission of the Estate Officer.
24. The Authority reserves to itself all mines and mineral whatever in or under the said site with all such rights and powers as may be necessary or expedient for the purpose of searching for, working, obtaining, removing and enjoying the same at all such times in such manner as the Authority shall think fit, with power to carry out any surface or any underground working and to let down the surface of all or any part of the said site and to sink pits, erect buildings, construct lines and generally appropriate and use surface of the said site for the purpose of doing all such things as may be convenient or necessary for the full enjoyment of the exceptions and reservations herein contained:

Provided that you shall be entitled to receive from the Authority such payment for the occupation by the Authority of the surface and for the damage done to the surface or building on the said land by such works or working or letting down as may be agreed upon between you and the Authority or failing such agreement as shall be ascertained by reference to Arbitration.
25. The Authority may by its officers and servants at all reasonable times and in a reasonable manner after 24 hours in writing enter in or upon any part of the said land/building erected thereon for the purpose of ascertaining that the allottee has duly performed and observed the conditions to be observed under the rule/ code/ regulations applicable under the said Act.
26. The Authority shall have full rights, power and authority at all times to do through its officers or servant all acts and things which may be necessary or expedient for the purpose of enforcing,

compliance with all or any of the terms, conditions and reservations imposed and to recover from you as first charge upon the said land/building, the cost of doing all or any such act and things and all cost incurred in connection therewith or in and any way relating thereto.

27. All disputes and differences arising out of or in any way touching or concerning this allotment whatsoever shall be referred to the sole arbitration of the Chief Administrator or any other officer appointed by him. It will not be an objection to such appointment that the arbitrator so appointed is a Government servant or an officer of the Authority that he had to deal with the matter to which this allotment relates in the course of his duties as such Government servant or officer, as the case may be, he has expressed his views on all or any of the matters in disputes or difference. The decision of such arbitrator shall be final and binding on the concerned parties.

Estate Officer

HUDA_____

Note.—

1. If the Allottee Appoints any attorney he/she shall submit the certified copy of the registered attorney along with photographs and signatures of the allottee and attorney duly attested by the magistrate within a week from the registration of the deed by Regd./A.D post or in person.
2. Any change in address must be intimated to this office within a week by registered A.D post or in person.
3. You are requested to submit affidavit of three specimen signatures and one stamp size photographs duly attested by the Executive Magistrate within a week for record of this office.
4. You are also requested to submit the Marital status of all the allottees *i.e.* Married/Unmarried/Single/Widow. In case of widow, the date of death of spouse may be intimated.

Registered

HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY

Estate Office, _____.

FORM "CC-B"*(See Regulation-6 (2))*(Form of Allotment letter, for allotment made on free-hold basis – Through e-auction
for booths/kiosks)

PHOTOGRAPH OF ALLOTTEE(S)

To

Memo No. : EO()/

Dated _____

Subject.— Allotment by sale of Booths/kiosks site/building No. _____ Situated in sector- _____ Urban Estate _____ on free hold basis.

Please refer to your bid for site/building No. _____ in Sector _____ Urban Estate _____ auctioned on as is where is basis.

2. Your bid for plot/building No. _____ in Sector _____ on _____ Urban Estates. _____ has been accepted and the plot/building as detailed below, has been allotted to you on free hold basis as per the following terms and conditions and subject to the provisions of the Haryana Urban Development Authority Act, 1977 (hereinafter referred to as the Act) and the Rules/ Regulations/ Code/ Instructions/ guidelines applicable thereunder and as amended from time to time including terms and conditions as already announced at the time of auction and accepted by you.

Sector No.	Name of Urban Estate	Plot/building No.	Approximate dimension or description as notified at the time of auction	Area (In sq.mtr.)	Price (in ₹.)

3. The sum of ₹. _____ deposited by you towards 10% of bid amount will be adjusted against the price of the plot/building.
4. Further you are requested to remit ₹. _____/- within 45 days *i.e* (upto _____) from the date of auction, which together with the amount already paid by you, will constitute 40% of the total bid price of said plot/building. In case of failure to deposit the said amount within the above specified period, the allotment shall be cancelled and the 10% bid money deposited at the time of bid shall stand forfeited to the Authority, against which you shall have no claim for damages.

5. Thereafter, remaining 60% amount of the total bid amount *i.e* ₹. _____/- of the above plot/building shall be paid in lumpsum within 60 days from the date of auction without interest or in 6 half yearly installments. First installment will fall due after expiry of 6 months from the date of issue of auction. Each installment would be recoverable together with interest @ 9% per annum the remaining amount as mentioned in clause No. 29 of this allotment letter. However, In case balance 60% amount of the total bid amount is paid in lump-sum within a period of 60 days from the date of auction, rebate of 5% in the total price will be allowed.
6. The possession of the plot/building is hereby offered to you which may be taken immediately after making payment of balance 30% amount as demanded in Sr. No. 4 above, as the development works (basic amenities) within the area are already complete. Development works for this purpose shall mean provision of basic amenities *i.e.* road upto WBM level, water, electricity and sewerage.
7. No separate notice will be sent for payment of the aforesaid payments.
8. All the payments/installments shall be made either through online payment on HUDA Website or through off line mode through authorized Banks by generating challan from PPM System on the HUDA website. The payment of installment (s) by due date is mandatory. In case, payment of installment (s) is not made by the due date, then you shall be liable to pay interest on the delayed payments. At present, the interest on delayed payment of installment is @ 12% p.a. simple. In future you shall have to pay the interest, simple or compound and at such rate, on the delayed payment of installments as decided by the Authority from time to time irrespective of the fact whether the possession has been offered or not without the prejudice to the rights of Authority to take action u/s 17 of HUDA Act.
9. In case the installment is not paid by due date, the Estate Officer shall proceed to take action for imposition of penalty & resumption of plot in accordance with the provisions of section 17 of the Act.
10. Wherever in case you surrender the site at any time prior to construction, the concerned Estate Officer, HUDA will refund the amount after deducting 10% of the total consideration money including interest and penalty if any due upto the date of application for such surrender. However, no interest shall be payable on the refunded amount.
11. The request for surrender has to be submitted online on the PPM system on HUDA Website by using the login id and password allotted by HUDA. Surrender by any other mode shall not be acceptable.
12. However, if due to stay by the Court or litigation or circumstances beyond its control, HUDA is not able to offer possession of the plot/site within three months after deposit of the entire bid amount and interest, the full amount deposited by you shall be refunded back with simple interest @ 5.5 % per annum to be calculated only on the bid amount paid by you. You will not have any claim, on this site/sites or any other alternate site-sites.
13. In the event of breach of any condition, the Estate Officer, HUDA may resume the site in accordance with the provisions of Section-17 of the Act and the money deposited shall be refunded back after forfeiting 10% of the total consideration money, interest and other dues payable upto the date of resumption. No interest will be paid on such amount to be refunded.
14. Upon resumption, You will be free to remove the structure/debris/fixtures, if any, within a period of three months of resumption order at your own cost, failing which it shall be removed by the HUDA at your cost.
15. The site shall continue to belong to HUDA on account of sale together with interest and other amount due to HUDA on account of sale of site is paid and deed of conveyance in your favour is executed. You shall have no right to transfer the site or create any right/title/interest thereon without prior written permission of the concerned Estate Officer, HUDA even after execution of Deed of Conveyance. You may however mortgage or create any right/interest on the site only to secure the loan amount against the plot towards payment of price including dues etc. of the plot but prior written permission of the concerned Estate Officer, HUDA shall be required.
16. On payment of 100% of the bid amount and interest etc. you shall get the deed of conveyance executed in your favour in the prescribed form and in such manner as may be directed by the concerned Estate Officer, HUDA. The deed of conveyance shall be executed within one year of making payment of full price of the plot/building. However, in case of failure to so execute the conveyance deed in one year period specified herein, the conveyance deed shall be executable on the stamp duty on value of site calculated on the collector rates prevailing in the year of such execution or auction price whichever is higher. The charges for the registration and stamp duty will be paid by you.

17. The conditions for erection of building on the auctioned site shall be governed by the zoning plan of the site or 'Standard Design' of the site and in accordance with the Haryana Building Code, 2016 as framed and amended from time to time. The building shall be erected after getting and plans approved from the respective Estate Office, HUDA. You shall not make any alterations/additions to the structure erected on the site without prior/explicit written permission of the Estate Officer.
18. The coverage (passage/verandah) in front of the site of booth/kiosks shall not be allowed for any other purpose other than for the public passage.
19. You will have to complete the construction within two years of the date of offer of possession after getting the plans of the proposed building approved from the competent authority in accordance with the rule/regulations/code governing the erection of buildings. The time limit is extendable by the Estate Officer, subject to payment of extension fee as fixed by HUDA from time to time, otherwise this plot is liable to be resumed and the whole or part of the money paid, if any, in respect of it is liable to be forfeited in accordance with the provision of the Act. You shall not erect any building or make any alteration/addition without prior permission of the Estate Officer.
20. The plot/building shall not used for any purpose other than that for which it has been allotted in accordance with the plans approved by the competent authority. No obnoxious trade shall be carried out in or on any land/building.
21. The site shall not be subdivided or fragmented under any circumstances.
22. You shall have to pay all general and local taxes, rates or cesses imposed or assessed on the said land/building by the competent authority.
23. You shall have to pay separately for any construction material, bricks, structures and compound wall etc. existing in your plot at the time of allotment of which compensation has been assessed and paid by the Authority, if you want to make use of the same.
24. The Authority will not be responsible for leveling the uneven site as the site has been auctioned on 'As is where is basis'.
25. The Authority reserves to itself all mines and mineral whatever in or under the said site with all such rights and powers as may be necessary or expedient for the purpose of searching for, working, obtaining, removing and enjoying the same at all such times in such manner as the Authority shall think fit, with power to carry out any surface or any underground working and to let down the surface of all or any part of the said site and to sink pits, erect buildings, construct lines and generally appropriate and use surface of the said site for the purpose of doing all such things as may be convenient or necessary for the full enjoyment of the exceptions and reservations herein contained:

Provided that the allottee shall be entitled to receive from the Authority such payment for the occupation by the Authority of the surface and for the damage done to the surface or building on the said land by such works or working or letting down as may be agreed upon between the allottee and the Authority or failing such agreement as shall be ascertained by reference to Arbitration.
26. The Authority may by its officers and servants at all reasonable times and in a reasonable manner after 24 hours in writing enter in or upon any part of the said land/building erected thereon for the purpose of ascertaining that the allottee has duly performed and observed the conditions to be observed under the rule/regulations applicable under the said Act.
27. The Authority shall have full rights, power and authority at all times to do through its officers or servant all acts and things which may be necessary or expedient for the purpose of enforcing, compliance with all or any of the terms, conditions and reservations imposed and to recover from you as first charge upon the said land/building, the cost of doing all or any such act and things and all cost incurred in connection therewith or in and any way relating thereto.
28. All disputes and differences arising out of or in any way touching or concerning this allotment whatsoever shall be referred to the sole arbitration of the Chief Administrator or any other officer appointed by him. It will not be an objection to such appointment that the arbitrator so appointed is a Government servant or an officer of the authority that he had to deal with the matter to which this allotment relates in the course of his duties as such Govt. servant or officer, as the case may be, he has expressed his views on all or any of the matters in disputes or difference. The decision of such arbitrator shall be final and binding on the concerned parties.

29. Half yearly installments will fall due on _____ & _____ of every year. The details of half yearly installments are as under:-

Installment No.	Principal (in ₹)	Possession interest (in ₹)	offer	Total (in ₹)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Estate Officer

HUDA_____

Note.—

1. If the Allottee Appoints any attorney he/she shall submit the certified copy of the registered attorney along with photographs and signatures of the allottee and attorney duly attested by the magistrate within a week from the registration of the deed by Regd/A/D post or in person.
2. Any change in address must be intimated to this office within a week by registered A/D POST OR IN PERSON.
3. You are requested to submit affidavit of three specimen signatures and one stamp size photographs duly attested by the Executive Magistrate within a week for record of this office.
4. You are also requested to submit the Marital status of all the allottees *i.e.* Married/Unmarried/Single/Widow. In case of widow, the date of death of spouse may be intimated.

Registered

HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY

Estate Office, _____.

FORM "CC-G"

(See Regulation-6 (2))

(Form of Allotment letter, for allotment made on free-hold basis through e-auction for preferential (GP/P/SP) residential/ institutional/commercial plots/building)

PHOTOGRAPH OF ALLOTTEE(S)

To

.....
.....
.....

Memo No. : EO ()/

Dated _____

Subject. — Allotment by sale of preferential (GP/P/SP)residential/ institutional/commercial site/building No. at _____ on free hold basis.

Please refer to your bid for site/building No. _____ in Sector _____, Urban Estate, _____ auctioned on as is where is basis.

2. Your bid for plot/building No. _____ in Sector _____ Urban Estate, _____ has been accepted and the plot/building as detailed below, has been allotted to you on free hold basis as per the following terms and conditions and subject to the provisions of the Haryana Urban Development Authority Act, 1977 (hereinafter referred to as the Act) and the Rules/Regulations/Code/Instructions/guidelines applicable thereunder and as amended from time to time including terms and conditions as already announced at the time of auction and accepted by you.

Sector No.	Name of Urban Estate	Plot/ building No.	Approximate dimension or description as notified at the time of auction	Area (In sq.mtr.)	Price (in ₹.)

3. The sum of ₹. _____ deposited by you towards bid money will be adjusted against the plot/building.
4. Further you are requested to remit ₹. _____/- within 45 days (upto _____) from the date of auction, which together with the amount already paid by you, will constitute 25% of the total bid price of said plot/building. In case of failure to deposit the said amount within the above specified period, the allotment shall be cancelled and the 10% bid money deposited at the time of bid shall stand forfeited to the Authority, against which you shall have no claim for damages.
5. Thereafter, remaining 75% amount of the total bid amount *i.e* ₹. _____/- of the above plot/building shall be paid in lumpsum within 120 days (for residential plots) or 180 days (for other categories) from the date of auction without interest, failing which this allotment shall stand cancelled without any notice and 25% bid money deposited by you shall stand forfeited and you shall have no claim for the damages.

6. No separate notice will be sent for payment of the aforesaid payments.
7. All payments shall be made either online on HUDA Website or off line mode through authorized Banks by generating challan from the HUDA website.
8. Wherever an allottee surrenders the site at any time within a period of 120 days (for residential plot) or 180 days (for other categories) from the date of auction, the concerned Estate Officer, HUDA will refund the amount after deducting 10% of the total consideration money including interest and penalty if any due upto the date of application for such surrender. However, no interest shall be payable on such amount to be refunded.
9. The request for surrender has to be submitted online on the PPM system on HUDA Website by using the login id and password allotted by HUDA. Surrender by any other mode shall not be acceptable.
10. The possession of the site/plot shall be offered only after full bid amount has been paid to HUDA by you. In case possession of the plot is not offered within a period of 30 days after deposit of full bid amount, HUDA will pay interest @ 5.5 % (or as may be fixed by Authority from time to time) on the amount deposited by you till the date of offer of possession. However, such interest shall be payable for the period calculated after expiry of 30 days as aforesaid and till the date of offer of possession.
11. However, if due to stay by the Court or litigation or circumstances beyond its control, HUDA is not able to offer possession of the plot/site within three months after deposit of full (100%) bid amount, the full amount deposited by you shall be refunded back. You will not have any claim on this site/sites or any other alternate site/sites.
12. In the event of breach of any condition, the Estate Officer, HUDA may resume the site in accordance with the provisions of section 17 of the Act and the money deposited shall be refunded back after forfeiting 10% of the total consideration money, interest and other dues payable upto the date of resumption. No interest shall be paid on such amount to be refunded.
13. Upon resumption, you will be free to remove the structure/debris/fixtures, if any, within a period of three months of resumption order at your own cost, failing which it shall be removed by the HUDA at your cost.
14. The site shall continue to belong to HUDA until the entire bid money together with interest and other amount due to HUDA on account of sale of site is paid and deed of conveyance in your favour is executed. You shall have no right to transfer the site or create any right/title/interest thereon without prior written permission of the concerned Estate Officer, HUDA even after execution of Deed of Conveyance. You may however mortgage or create any right/interest on the site only to secure the loan amount against the plot towards payment of price including dues etc. of the plot but prior written permission of the concerned Estate Officer, HUDA shall be required.
15. On payment of 100% of the bid amount and interest, if any, etc., you shall get the deed of conveyance executed in your favour in the prescribed form and in such manner as may be directed by the concerned Estate Officer, HUDA. The deed of conveyance shall be executed within one year of making payment of full price of the plot/ building. However, in case of failure to so execute the conveyance deed in one year period specified herein, the conveyance deed shall be executable on the stamp duty on value of site calculated at the prevailing collector rates prevailing in the year of its execution or auction price whichever is higher. The charges for the registration and stamp duty will be paid by you.
16. The site shall not be used for any purpose other than that for which it has been allotted. No obnoxious activity shall be carried out on the site. However, as per HUDA Regulations, 1978 and policy issued there-under and amended from time to time, non nuisance professional consultancy services are permitted in case of residential plots only.
17. The site shall not be subdivided or fragmented under any circumstances. However, registration of independent floors is permitted as per policy in case of residential plots only.
18. You shall have to pay all general and local taxes, rates or cesses imposed or assessed on the said land/building by the competent authority.
19. You shall have to pay separately for any construction material, bricks, structures and compound wall etc. existing in your plot at the time of allotment of which compensation has been assessed and paid by the Authority, if you want to make use of the same.
20. The Authority will not be responsible for leveling sites as site has been auctioned on as is where is basis.
21. The conditions for erection of building on the auctioned site shall be governed by the zoning plan of the site and in case of commercial site also by 'Standard Design', in accordance with the Haryana Building Code, 2016 as framed and amended from time to time. The building shall be erected after getting the

- plans approved from the respective Estate Officer, HUDA. You shall not make any alterations/additions to the structure erected on the site without prior/explicit written permission of the Estate Officer.
22. In case of commercial sites, the coverage (passage/verandah) in front of on the site of booths/shop cum-flats/shop cum-office etc. shall not be allowed for any other purpose other than the public passage.
 23. You will have to complete the construction within two years of the date of offer of possession after getting the plans of the proposed building approved from the competent authority in accordance with the regulations governing the erection of buildings. The time limit is extendable by the Estate Officer, subject to payment of extension fee as fixed by HUDA from time to time, otherwise this plot is liable to be resumed and the whole or part of the money paid, if any, in respect of it is liable to be forfeited in accordance with the provision of the Act. You shall not erect any building or make any alteration/addition without prior permission of the Estate Officer.
 24. The Authority reserves to itself all mines and mineral whatever in or under the said site with all such rights and powers as may be necessary or expedient for the purpose of searching for, working, obtaining, removing and enjoying the same at all such times in such manner as the Authority shall think fit, with power to carry out any surface or any underground working and to let down the surface of all or any part of the said site and to sink pits, erect buildings, construct lines and generally appropriate and use surface of the said site for the purpose of doing all such things as may be convenient or necessary for the full enjoyment of the exceptions and reservations herein contained:

Provided that the allottee shall be entitled to receive from the Authority such payment for the occupation by the Authority of the surface and for the damage done to the surface or building on the said land by such works or working or letting down as may be agreed upon between the allottee and the Authority or failing such agreement as shall be ascertained by reference to Arbitration.
 25. The Authority may by its officers and servants at all reasonable times and in a reasonable manner after 24 hours in writing enter in or upon any part of the said land/building erected thereon for the purpose of ascertaining that the allottee has duly performed and observed the conditions to be observed under the rule/code/regulations applicable under the said Act.
 26. The Authority shall have full rights, power and authority at all times to do through its officers or servant all acts and things which may be necessary or expedient for the purpose of enforcing, compliance with all or any of the terms, conditions and reservations imposed and to recover from you as first charge upon the said land/building, the cost of doing all or any such act and things and all cost incurred in connection therewith or in and any way relating thereto.
 27. All disputes and differences arising out of or in any way touching or concerning this allotment whatsoever shall be referred to the sole arbitration of the Chief Administrator or any other officer appointed by him. It will not be an objection to such appointment that the arbitrator so appointed is a Government servant or an officer of the authority that he had to deal with the matter to which this allotment relates in the course of his duties as such Govt. servant or officer, as the case may be, he has expressed his views on all or any of the matters in disputes or difference. The decision of such arbitrator shall be final and binding on the concerned parties.

Estate Officer
HUDA_____

Note.—

1. If the Allottee Appoints any attorney he/she shall submit the certified copy of the registered attorney along with photographs and signatures of the allottee and attorney duly attested by the magistrate within a week from the registration of the deed by Regd/A/D post or in person.
2. Any change in address must be intimated to this office within a week by registered A/D post or in person.
3. You are requested to submit affidavit of three specimen signatures and one stamp size photographs duly attested by the Executive Magistrate within a week for record of this office.
4. You are also requested to submit the Marital status of all the allottees *i.e.* Married/Unmarried/Single/Widow. In case of widow, the date of death of spouse may be intimated.

[71-1]